IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार में बेरोजगारी की समस्या एवं इससे प्रभावित जीवन स्तर का विश्लेषण

अंजलि चन्द्रा * एवं डॉ० पुष्पा सिन्हा **

*** शोधार्थी, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार**

****एसोसिएट प्रो०, मगध महिला कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार**

सारांश

आर्थिक विकास की मूल शर्त अर्थव्यवस्था में उपस्थित संसाधनों का संपूर्ण उपयोग है । संसाधनों में पूँजी एवं भूमि का स्थान तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही मानव पूँजी का भी विशेष स्थान है । यदि मानव पूँजी का समुचित उपयोग कर लिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में विद्यमान प्रत्येक श्रमबल को उनके श्रम के अनुरुप पारिश्रमिक मिल जाता है । फलतः रोजगार को प्राप्त मानव पूँजी का विकास हो जाता है, साथ ही राष्ट्र के आर्थिक विकास के नवीन आयाम का परिदृश्य भी स्पष्ट हो जाता है । बेरोजगारी की समस्या अर्थव्यवस्था में उपस्थित कार्य करने को इच्छुक श्रमबल को व्यर्थ कर देती है । यह समस्या मानव पूँजी को न केवल आर्थिक क्षति पहुँचाती है, बल्कि समाज के मध्य उन्हें मानसिक रुप से निरंतर उत्पीड़ित करती रहती है । बेरोजगारी का प्रभाव उपभोग व्यय, बचत करने की क्षमता एवं निवेश की प्रेरणा पर भीषण रुप से पड़ता है जिससे जीवन स्तर प्रभावित होता है । आय के एक निर्बाध स्त्रोत के अभाव में व्यक्ति उपभोग व्यय, बचत व निवेश को निम्न स्तर का बनाए रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था का विस्तार नहीं हो पाता है और राष्ट्र के प्रगति का मार्ग संकुचित हो जाता है ।

शब्द कुंजी – बेरोजगारी, आर्थिक संकट, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जीवन स्तर पर प्रभाव ।

परिचय

' बेरोजगारी ' – अंतर्मन को झकझोर कर रख देने वाला एक शब्द । वास्तव में यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विकासशील देश की आत्मा को कमजोर बनाने वाला सामाजिक अभिशाप है, जो तीव्र गति से अपने अस्तित्व को मजबूत बनाता जा रहा है । अद्यतन आँकड़ों की ओर यदि ध्यान आकर्षित करें, तो हम अपने समृद्धशाली भारत देश को बेरोजगारी की समस्या से जूझता हुआ पाते हैं । बेरोजगारी भारत की संपन्नता के मार्ग में उत्पन्न होने वाले व्यवधानों में प्रमुख रूप से चिंतनीय है । हमारा देश मानव संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में संपूर्ण विश्व में दूसरे स्थान का आनंद उठाता है, लेकिन मानव संसाधनों के पूर्ण उपयोग की कुशलता की कमी देश की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचाती है । दूसरे शब्दों में, बेरोजगारी मानव संसाधन की क्षति है, जो भारत को विश्व पटल पर विकसित राष्ट्र की भूमिका निभाने के मार्ग में पीछे की ओर ढ़केलता है । भारत में बेरोजगारी का स्वरूप विश्व के अन्य उन्नत राष्ट्रों से बिल्कुल अलग है । विकसित राष्ट्र चक्रिय बेरोजगारी से ग्रसित हैं, यद्यपि हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुपक्षीय परिदृश्य है, जो दिन–प्रतिदिन गंभीर रूप धारण करता जा रहा है । वास्तव में जब कोई व्यक्ति योग्यता होने एवं कार्य करने की इच्छा रखने के बाद भी स्वयं को रोजगार से वंचित पाता है, तो यह बेरोजगारी की भयावह स्थिति को प्रकट करता है । साधारण शब्दों में, बेरोजगारी का शाब्दिक अर्थ है, किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार के उत्पादक कार्य में नियोजित नहीं होना । भारत देश बेरोजगारी के अलग–अलग स्वरूपों से जूझ रहा है, जिनमें मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शैक्षणिक बेरोजगारी प्रमुख रूप से देश की अर्थव्यवस्था को कुप्रभावित करती है।

साहित्य समीक्षा

चौधरी डी० के० (2021) के अनुसार, ' बेरोजगारी की समस्या ने कई गंभीर समस्याओं जैसे गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, झुग्गी–झोपड़ी व अवैध बस्तियों के प्रसार, असमानता, अपराध, बालश्रम, भिक्षावृत्ति आदि को उत्पन्न कर दिया है । बेरोजगारी को नौकरियों की माँग एवं इसकी आपूर्त्ति के बीच के अंतर के रुप में माना जा सकता है । भारत में बेरोजगारी की उच्च दर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है । बिहार राज्य देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जिसने जून 2019 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय राष्ट्रीय बेरोजगारी में भारी वृद्धि को दर्ज किया । वर्तमान पेपर बिहार में बेरोजगारी

की स्थिति से पीड़ित मुद्दों पर चर्चा करता है और और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए संभावित रणनीतिक हस्तक्षेपों द्वारा बेरोजगारी की स्थिति में सुधार हेतु रणनीति के निर्माण की बात करता है । अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा कई नीतियाँ प्रारंभ की गई हैं और ग्रामीण कृषि समाज में मनरेगा, स्टार्ट अप इंडिया, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन आदि विशिष्ट रुप से विद्यमान है, किंतु फिर भी शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है । '

कुमार ए० एवं कुमार एम० (2020) ने बेरोजगारी की समस्या से उत्पन्न हुई पलायन की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लेख प्रस्तुत किया है । बिहार से आजीविका की तलाश में पलायन कई दशकों से सामान्य हो गया है। पलायन के संदर्भ में बिहार राज्य शीर्ष स्थान पर है । बिहार में बेरोजगारी की दर देश के औसत से अधिक है । कम पैदावार, बढ़ती भूमिहीनता और राज्य द्वारा वित्तीय सहायता की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में कृषि अलाभकारी हो गई है । पलायन रोकने हेतु कृषि और गैर कृषि रोजगार उत्पन्न किया जाए । 2011 की गणना के अनुसार, 7.5 मिलियन प्रवासियों ने बिहार को एक मूल राज्य के रुप में बताया, जहाँ से उन्होंने पलायन किया । प्रवासियों की अधिकतम संख्या ने रोजगार की तलाश को प्रवास का कारण बताया ।

सबरीन एम० एवं बेहेरा डी० के० (2020) के अनुसार, ' भारत में बिहार कम विकसित राज्यों में से एक रहा है, किंतु वर्तमान के वर्षों में एक प्रभावशाली विकास की बनावट दिख रही है । बिहार की आर्थिक संरचना बदल रही है, साथ ही साथ श्रम रोजगार की बनावट भी कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो रही है। 2004 और 2017–2018 के बीच कृषि में कार्यरत कर्मचारियों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत हो गई है, जबकि उद्योगों और सेवाओं में रोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र, जो कृषि रोजगार का एक बड़ा हिस्सा है, ने भी गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि देखी है, हालांकि यहाँ बेरोजगारी की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। नवीनतम पीएलएफएस PLFS (2017-2018) डेटा सेट का उपयोग करते हुए, यह पेपर बिहार में विभाजन के बाद से संरचनात्मक परिवर्तन का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलते रोजगार संरचना ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। '

चक्रवर्ती बी० (2019) के अनुसार, ' भारत में, देश की जनसंख्या का 54 प्रतिशत भाग 25 वर्ष से कम आयु वर्ग से है और छिपी हुई बेरोजगारी के उच्च दर का सामना कर

रहा है । युवा रोजगार बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किए गए । प्रशिक्षण कार्यक्रम लक्षित समूह ग्रामीण गरीब युवाओं तक पूरी तरह से पहुँचता तो है, किंतु 2 से 6 महीने बाद, कार्यक्रम का रोजगार प्रभाव शून्य हो जाता है । वेतन और उनके प्रव्रजित होकर रहने की लागत के बीच बेमेल होने के कारण मिला हुआ रोजगार भी छोड़ दिया जाता है ।

सिन्हा जे० के० (2019) द्वारा प्रस्तुत पेपर में 1990-2019 की अवधि में बिहार में समय श्रृंखला के आंकड़ों के आधार पर उत्पादन वृद्धि पर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के प्रभावों की जाँच की गई है । युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास के साथ बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में भौतिक पूँजी विस्तार और मानव पूँजी की संभावित उत्पादकता को बढ़ाना एवं आर्थिक विकास को सकारात्मक रुप से प्रभावित करना प्रमुख निर्धारक प्रतीत होता है ।

देशवाल ए० (2017) ने अपने लेख में 2004 से 2012 तक के आंकड़ों को आधार बनाया है । 2004-2005 से पहले की अवधि के रोजगार के पैटर्न को जोड़ने और उपभोग के क्षेत्र में सामने आए विकृत विकास को ध्यान में रखते हुए, ऐसे पैटर्न का पता चलता है जो गरीबी में कमी की दरों के साथ सामंजस्य बिठाने में समस्या उत्पन्न करती है । भोजन पर प्रति व्यक्ति व्यय सभी वर्गों में घट रहा है और श्रम शक्ति अधिक से अधिक हाशिए पर जा रही है ।

श्रीनिवासन टी० एन० एवं ऐलन टी० (2013) द्वारा भारत में 1970 के शुरुआत से रोजगार एवं बेरोजगारी के रुझानों का विश्लेषण किया गया । यद्यपि रोजगार व बेरोजगारी के आंकड़ों के कई स्त्रोत विद्यमान हैं किंतु समय के साथ सभी स्त्रोतों में रोजगार की स्थिति समान नहीं है । इसके अलावा, अधिकांश स्त्रोतों में जानकारी कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है । NSSO के राष्ट्रीय पंचवर्षीय घरेलू सर्वेक्षण में अनिवार्य रुप से रोजगार और बेरोजगारी की समान अवधारणाओं का उपयोग किया गया था । केरल और बिहार राज्य के अध्ययन के निष्कर्ष में बिहार की स्थिति बेहद परेशान करने वाली है । बिहार ने भारत के वैश्वीकरण से महत्वपूर्ण रुप से लाभ को प्राप्त नहीं किया है ।

वेंकटेश पी० (2013) ने अपने पेपर में भारतीय अर्थव्यवस्था के संक्रमण के संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तीन विशेषताओं – ग्रामीण रोजगार पैटर्न में बदलाव, ग्रामीण मजदूरी और कृषि विकास में रुझान एवं कृषि मजदूरी व उत्पादकता के बीच संबंध की जाँच की है । 2009-2010 में ग्रामीण गैर कृषि रोजगार क्षेत्र ने लगभग 38 प्रतिशत पुरुष

और 21 प्रतिशत महिला श्रम बलों को रोजगार प्रदान किया । ग्रामीण गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में निर्देशित नीतियाँ बेहतर मजदूरी दर प्रदान करेंगी ।

कश्यप के० (2005) के अनुसार, ' बेरोजगारी और गरीबी का दुश्चक्र बिहार की अर्थव्यवस्था को घेर रहा है । गैर – कृषि व्यवसायों ने अभी तक अपनी बढ़ती जनसंख्या को अवशोषित नहीं किया है । उत्तर और मध्य बिहार में कई समस्याएँ हैं, जिनमें बाढ़, शिक्षा का निम्न स्तर प्रमुख है जिससे कि न तो बेरोजगारी कम हो रही है और न ही निर्धनता । '

भट्टाचार्य बी० (2000) के अनुसार, ' बिहार के विभाजन ने राज्य के भविष्य पर पहले से ही व्यापक चिंता को और बढ़ा दिया है । विभाजन ने बिहार के भविष्य के प्रश्न को ला खड़ा किया है । झारखंड एवं बिहार के विभाजन ने बिहार के विकास की वास्तविकता को प्रकट कर दिया है । भविष्य की समस्याओं में बेरोजगारी एवं आर्थिक संकट को प्रमुख रुप से सम्मिलित किया गया है ।

अध्ययन की विधि

इस आलेख में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों में गुगल स्कॉलर, इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीक्ली, एग्रीकल्चरल इकॉनोमिक्स रिसर्च रिव्यू, द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकॉनोमिक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार के नीति एवं योजना आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों तथा टिप्पणी का उपयोग किया गया है । एम० एस० वर्ड का प्रयोग तालिका निर्माण हेतु किया गया है । प्रतिशत व अनुपात विधि से डेटा के विश्लेषण का कार्य पूर्ण हुआ है । लेखाचित्र के निर्माण में एम० एस० एक्सेल का सहयोग लिया गया है ।

बेरोजगारी की संकल्पना का साधारण परिचय

बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है, जो उन व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जो रोजगार योग्य हैं और सक्रिय रुप से नौकरी की तलाश भी कर रहे हैं, किंतु फिर भी रोजगार को प्राप्त कर पाने में असफल एवं असमर्थ हैं । इस समूह में वे सभी लोग सम्मिलित हैं, जो कार्यबल श्रेणी में तो आते हैं किंतु उनके पास उपयुक्त रोजगार नहीं है । बेरोजगारी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के संकेतकों में से एक के रुप में अपना कार्य करती है । शिक्षा का निम्न स्तर, विकलांगता तथा व्यक्तिगत मुद्दों से प्रभावित व्यक्तियों

को रोजगार प्राप्त करने हेतु रोजगारपरक नहीं माना जा सकता है । ऊपर उल्लिखित श्रेणी बेरोजगार लोगों की वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करती है ।

श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (बीएलएस) ने 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, जिनके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, को बेरोजगार की श्रेणी में स्थान प्रदान किया है । इस श्रेणी के भीतर एक और श्रेणी आती है, जिसमें व्यक्ति द्वारा 12 महीने सक्रिय रुप से रोजगार की तलाश की जाती है, किंतु अंतिम के चार सप्ताह में रोजगार की तलाश छोड़ दी जाती है, इसे ' हतोत्साहित श्रमिक ' कहा जाता है । (श्रम सांख्यिकी ब्यूरो 2022)

अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार ' बेरोजगारी की स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का संबंध एक विशिष्ट समय एवं उम्र सीमा के भीतर कार्य के अभाव, कार्य का उचित पारिश्रमिक न मिलने अथवा स्वरोजगार के न होने से है । ' (अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन 2013)

एडमंड एस० फेल्प्स जो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं नोबेल विजेता हैं, ने समष्टि आर्थिक नीतियों के विश्लेषण हेतु मुद्रास्फीति, मजदूरी एवं बेरोजगारी को विशेष रुप से प्रयुक्त किया तथा समष्टि आर्थिक नीतियों की व्याख्या की है । (एडमंड एस० फेल्प्स 2006)

तालिका 1

भारत एवं बिहार में शहरी बेरोजगारी की दर (प्रति 1000)

क्षेत्र	1993–94	1999–2000	2004–05	2009–10	2011–12	2017–18	2018–19
बिहार	71	74	64	73	56	90	105
भारत	45	47	45	34	34	78	77

स्त्रोत : एन० एस० एस० ओ० इंपलॉयमेंट एण्ड अनइंपलॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट, नीति आयोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (*PLFS*) , NSO

बेरोजगारी की स्थिति शहरी क्षेत्र में विभिन्न समय में भिन्न – भिन्न आंकड़ों के रुप में प्रकट हुई है । 1993–94 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 71 व्यक्ति एवं भारत में 45 व्यक्ति बेरोजगार पाए गए । 1999–2000 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 74 व्यक्ति एवं भारत में 47 व्यक्ति बेरोजगार थे । 2004–05 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 64 व्यक्ति

एवं भारत में 45 व्यक्ति बेरोजगार थे । वही 2009–10 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 73 व्यक्ति एवं भारत में 34 व्यक्ति बेरोजगार थे । 2011–12 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर 56 व्यक्ति एवं भारत में 34 व्यक्ति बेरोजगार थे । 2017–18 की समय अवधि में बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर 90 व्यक्ति एवं भारत में 78 व्यक्ति रोजगार के अभाव में जीवन यापन करने को विवश थे । 2018–19 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 105 व्यक्ति एवं भारत में 77 व्यक्ति बेरोजगार थे । भारत की तुलना में बिहार में बेरोजगारों की संख्या काफी अधिक है ।

अन्य राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की तुलना में बिहार में बेरोजगारी की स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है । 2018 – 19 के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में बेरोजगारी का स्तर केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि से कई अधिक है । सभी राज्यों में से सबसे अधिक बेरोजगारी नागालैंड (211) में है तथा सबसे कम बेरोजगारी की अवस्था को प्राप्त राज्य गुजरात (32) है ।

लेखाचित्र 1

विभिन्न राज्यों में शहरी बेरोजगारी की दर (प्रति 1000)

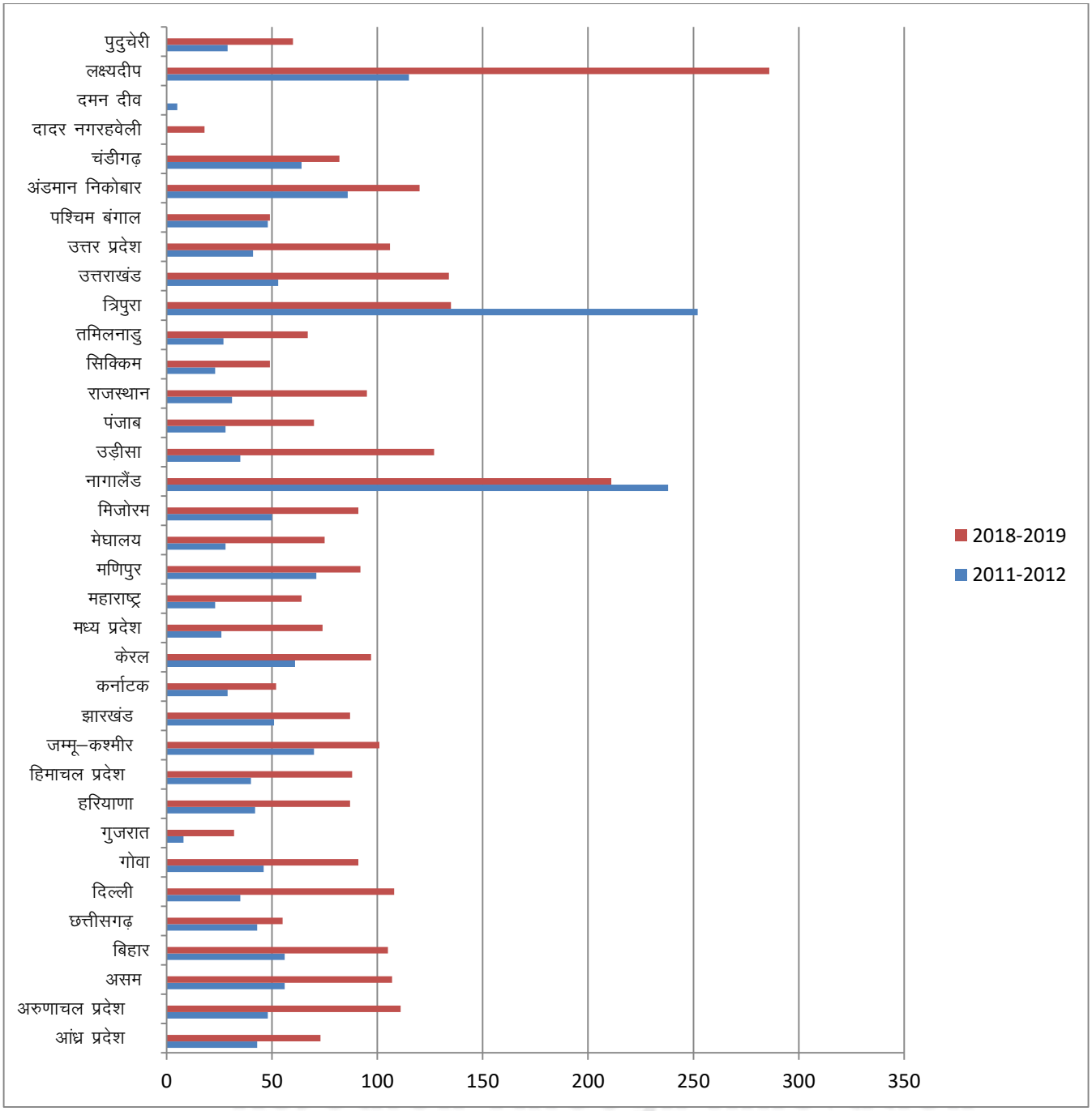

स्त्रोत : एन० एस० एस० ओ० इंपलॉयमेंट एण्ड अनइंपलॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट, नीति आयोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (*PLFS*) , NSO

तालिका 2

भारत एवं बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की दर (प्रति 1000)

क्षेत्र	1993–94	1999–2000	2004–05	2009–10	2011–12	2017–18	2018–19
बिहार	16	18	15	20	32	70	102
भारत	12	15	17	16	17	53	50

स्त्रोत : एन० एस० एस० ओ० इंपलॉयमेंट एण्ड अनइंपलॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट, नीति आयोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) , NSO

बेरोजगारी की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न समय में भिन्न – भिन्न आंकड़ों के रुप में स्पष्ट हुई है । 1993–94 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 16 व्यक्ति एवं भारत में 12 व्यक्ति बेरोजगार पाए गए । 1999–2000 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 18 व्यक्ति एवं भारत में 15 व्यक्ति बेरोजगार थे । 2004–05 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 15 व्यक्ति एवं भारत में 17 व्यक्ति बेरोजगार थे । वही 2009–10 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 20 व्यक्ति एवं भारत में 16 व्यक्ति बेरोजगार थे । 2011–12 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर 32 व्यक्ति एवं भारत में 17 व्यक्ति बेरोजगार थे । 2017–18 की समय अवधि में बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर 70 व्यक्ति एवं भारत में 53 व्यक्ति रोजगार के अभाव में जीवन यापन करने को विवश थे । 2018–19 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 102 व्यक्ति एवं भारत में 50 व्यक्ति बेरोजगार थे । भारत की तुलना में बिहार में ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या दुगुनी से भी अधिक है ।

बेरोजगारी की अवस्था के संदर्भ में यदि ग्राम एवं शहर के बीच तुलना की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेरोजगारी की दर कम है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शहरी बेरोजगारी की दर ग्रामीण बेरोजगारी से अधिक है । किंतु ग्रामीण बेरोजगारी की दर का शहरी बेरोजगारी की तुलना में कम होने का कारण छिपी हुई बेरोजगारी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ श्रमिक को यह भी ज्ञात नहीं होता है कि उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य है एवं वे छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं । इस परिस्थिति में यदि कार्य क्षेत्र से कुछ श्रमिकों को रोजगार से मुक्त भी कर दिया जाए तब भी उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

लेखाचित्र 2

विभिन्न राज्यों में ग्रामीण बेरोजगारी की दर (प्रति 1000)

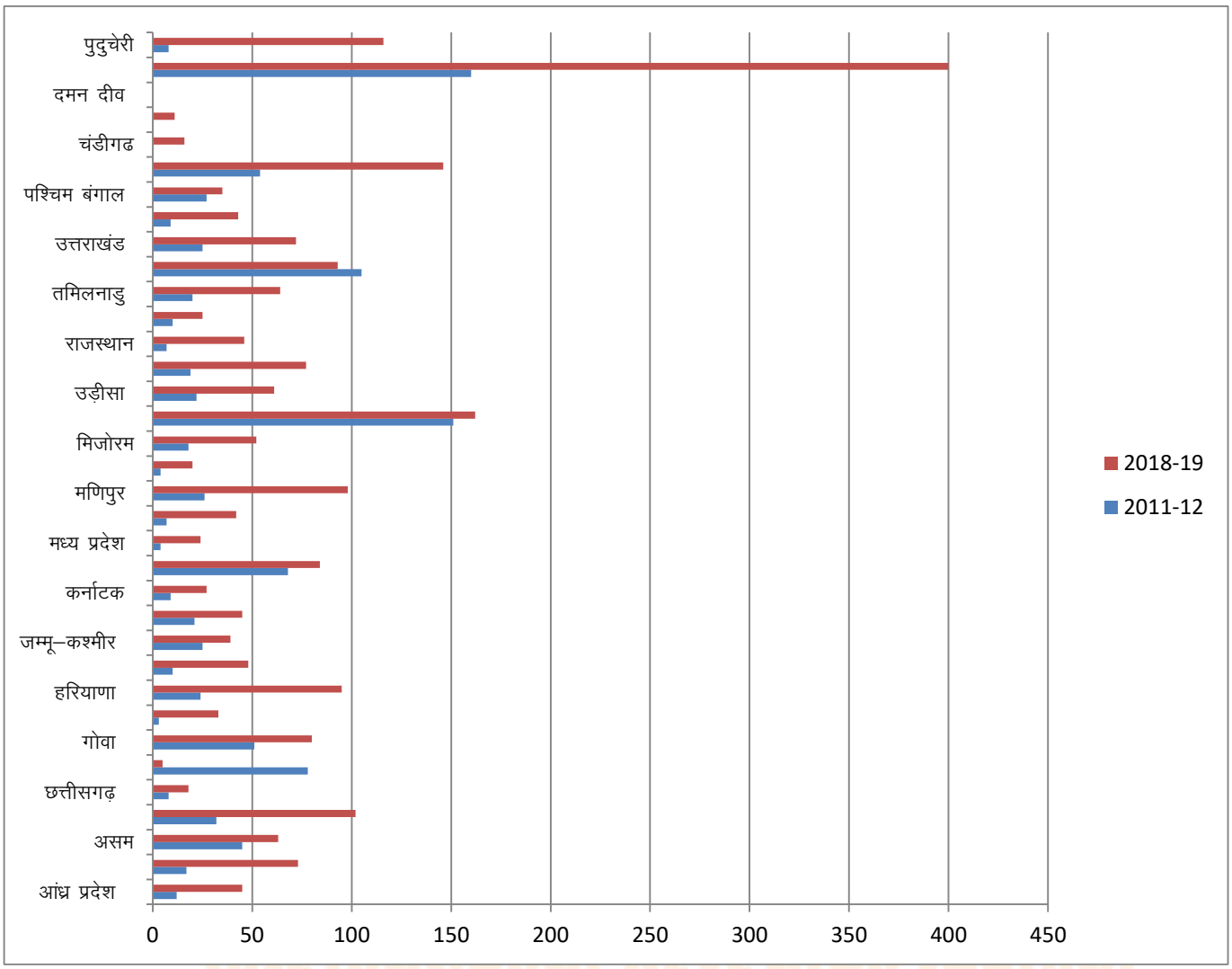

स्त्रोत : एन० एस० एस० ओ० इंपलॉयमेंट एण्ड अनइंपलॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट, नीति आयोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) , NSO

बेरोजगारी का जीवन स्तर पर प्रभाव

बेरोजगारी की समस्या का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव के जीवन स्तर पर पड़ता है । बेरोजगारी की समस्या से जीवन का स्तर निम्न हो जाता है । उपभोग का स्तर एवं व्यय का स्तर भी निम्न कोटी का होता है क्योंकि उपभोग व व्यय के लिए आय की आवश्यक्ता होती है । रोजगार के अभाव में आय का कोई स्त्रोत उपलब्ध नहीं हो पाता है और फिर यही अभाव जीवन को कई प्रकार से अवरुद्ध करके समाज में आर्थिक विषमता को उत्पन्न कर देते हैं । बेरोजगारी से जीवन स्तर बुरी तरह प्रभावित होकर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं नैतिकता आदि के स्तर को भी निम्न कर देता है । स्वास्थ्य का

निम्न स्तर आर्थिक संकट को और भी गहरा कर देता है । रोजगार की कमी से नैतिक पत्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई अनैतिक कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं ।

बेरोजगारी से आय, उपभोग व्यय एवं बचत का चक्र बाध्य हो जाता है । आय का अभाव उपभोग को कम कर देता है फलतः व्यय की मात्रा कम हो जाती है और बचत भी शून्य हो जाता है, जिससे आर्थिक क्रियाओं का सुचारु रुप से चल पाना बहुत ही कठिन हो जाता है । विलासिता की वस्तुओं को क्रय करना तो संभव ही नहीं होता है, साथ ही अनिवार्य वस्तुओं का भी उपभोग कर पाना मुश्किल हो जाता है ।

बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति के पास आय स्त्रोत नहीं होने से उसके जीवन में आर्थिक समस्या तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक एवं मानसिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है । बेरोजगारी की स्थिति से निकलने के लिए व्यक्ति कभी – कभी अनैतिक कार्यों तक को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में राष्ट्र का विकास असंभव हो जाता है । बेरोजगार व्यक्तियों के उपभोग व्यय का स्तर बहुत ही न्यूनतम होता है । उपभोग व्यय के लिए बेरोजगार व्यक्ति अपनी बचत का प्रयोग करते हैं जो कि निश्चित रुप से अल्प काल में ही समाप्त हो जाएगी । इस स्थिति को परिवर्तित करने का एक ही सरल मार्ग है और वह यह है कि व्यक्तियों को रोजगार प्राप्तक के स्थान पर रोजगार सृजक बनना होगा तभी बेरोजगारी की स्थिति में सुधार संभव हो सकेगा । भारत में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय को निम्नांकित तालिका के माध्यम से प्रकट किया गया है ।

तालिका 3

भारत में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय (रुपए में)

वर्ष	प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय
1974	44.170
1978	68.890
1982	112.310
1988	158.100
1994	281.400
2000	486.160

2006	558.780
2010	927.700
2012	1278.940

स्त्रोत : WWW.CEICDATA.COM | National Sample Survey Organisation

लेखाचित्र 3

भारत में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय (रुपए में)

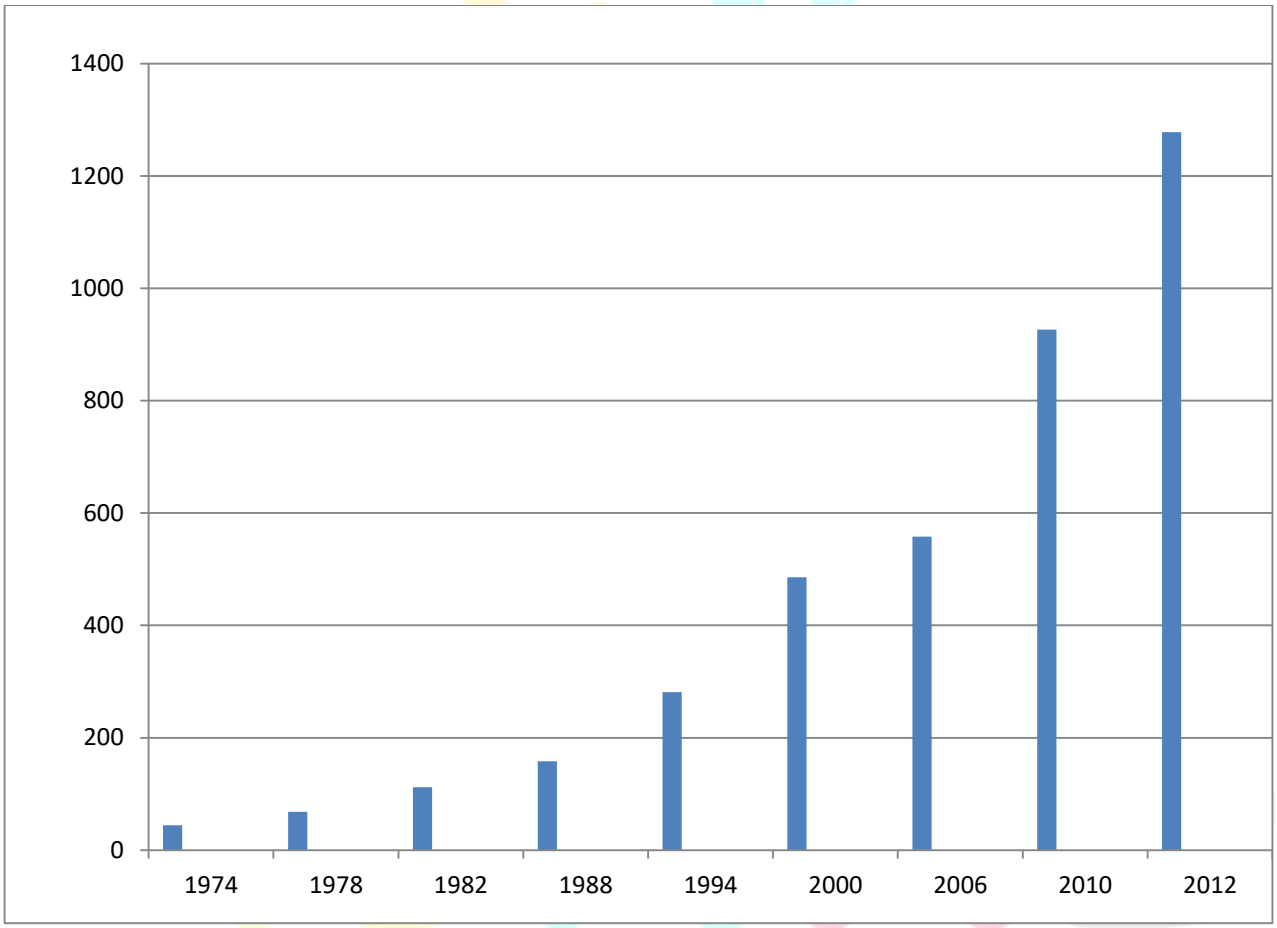

स्त्रोत : WWW.CEICDATA.COM | National Sample Survey Organisation

उपरोक्त तालिका एवं लेखाचित्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि 1974 से 2012 तक में भारत में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय में वर्ष दर वर्ष वृद्धि तो हो रही है, किंतु यह वृद्धि किसी विकसित राष्ट्र कि तुलना में बहुत ही कम है । किसी व्यक्ति द्वारा एक संपूर्ण माह में मात्र 1278 रुपए खर्च करना उसके आर्थिक संकट की ओर ध्यान आकृष्ट करता है ।

तालिका 4

भारत में निजी अंतिम उपभोग व्यय (करोड़ रुपए में)

वर्ष	भारत में निजी अंतिम उपभोग व्यय (करोड़ रुपए में)
2016-2017	53200
2017-2018	55800
2018-2019	59400
2019-2020	62200
2020-2021	55800

स्त्रोत : Centre for Monitoring Indian Economy Pvt. Ltd.

लेखाचित्र 4

भारत में निजी अंतिम उपभोग व्यय (करोड़ रुपए में)

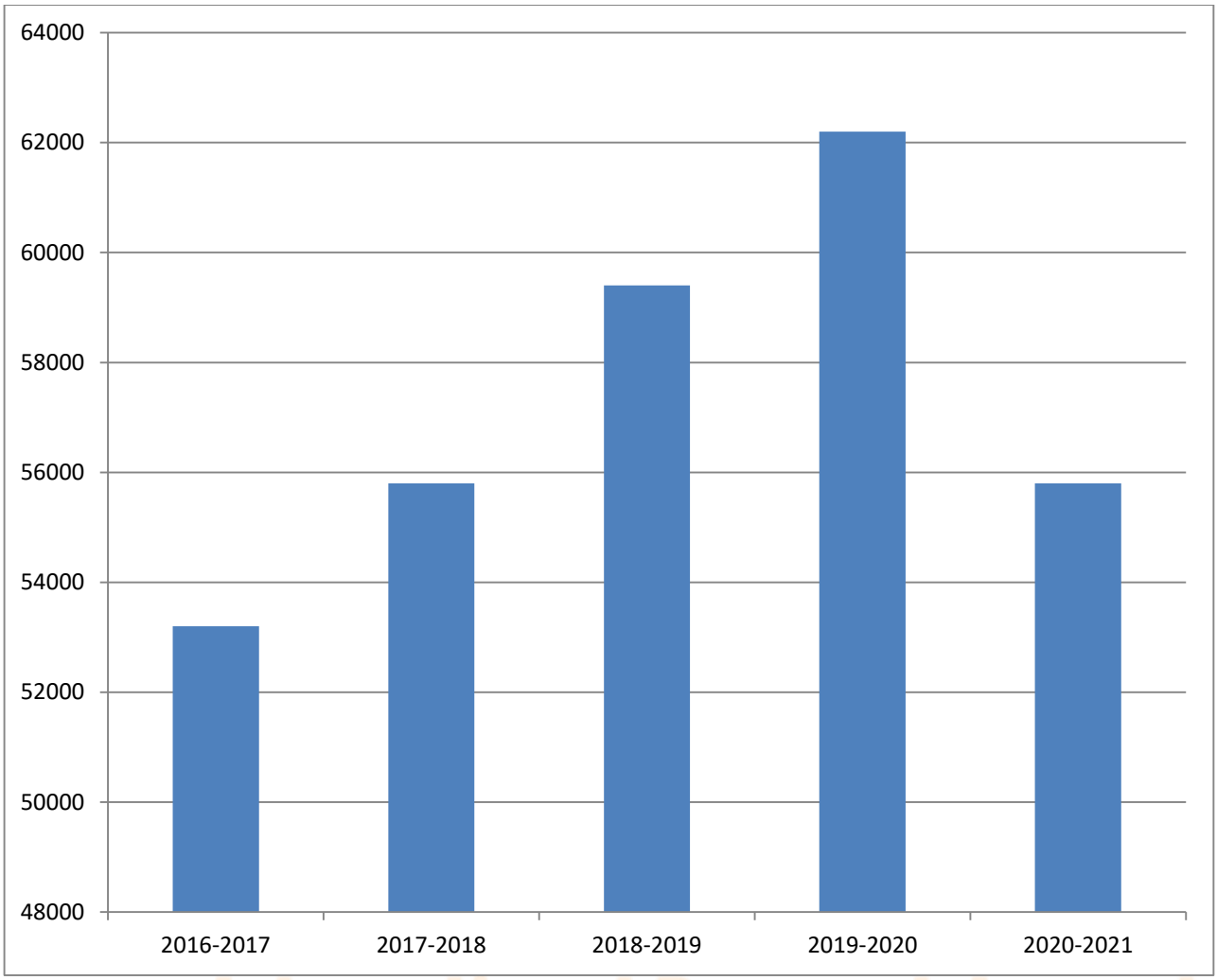

स्त्रोत : Centre for Monitoring Indian Economy Pvt. Ltd.

उपरोक्त तालिका एवं लेखाचित्र के द्वारा वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक में भारत देश में निजी अंतिम उपभोग व्यय 53200 करोड़ रुपए से बढ़कर 55800 करोड़ रुपए हो गई है, किंतु यदि वर्ष 2016 से वर्ष 2021 के बीच के वर्षों में भारत की निजी अंतिम उपभोग व्यय की गणना की जाए, तो यह क्रमिक रुप से विकसित होकर 53200 से 55800, 55800 से 59400 एवं 59400 से 62200 हो गई । 2019–2020 के बाद निजी अंतिम उपभोग व्यय में गिरावट देखी गई । यह गिरावट इतनी वृहद् थी, कि इसने अपने तीन वर्ष पूर्व के उपभोग व्यय स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया । इसके फलस्वरुप निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि के जिस मार्ग को 2017 से 2020 तक में तय कर लिया गया था, उसी उपभोग व्यय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः लौट गई । उपभोग व्यय में इस गिरावट का मुख्य कारण बेरोजगारी की समस्या रही, जिससे कि नवीन पूँजी का

संचार अवरुद्ध हो गया साथ ही उपभोग व्यय के स्तर में भी कमी आ गई । उपभोग व्यय की कमी ने निवेश की मात्रा को भी कुप्रभावित कर दिया ।

निष्कर्ष

बेरोजगारी की समस्या को निष्कर्ष रुप में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है कि रोजगार के अभाव की समस्या ने राष्ट्र की श्रम शक्ति को बुरी तरह से प्रभावित किया है । इसने न केवल श्रम शक्ति के वर्तमान को बर्बाद किया है, बल्कि इनके भविष्य को भी संकट में डाल दिया है । इस समस्या का प्रसार क्षेत्र ग्राम से लेकर शहर तक भिन्न – भिन्न दरों पर है, किंतु बेरोजगारी सभी स्थान पर विद्यमान है । शहरी क्षेत्र में यह शैक्षणिक एवं औद्योगिक बेरोजगारी के रुप में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में यह मौसमी बेरोजगारी एवं अदृश्य अथवा छिपी हुई बेरोजगारी के रुप में दृष्टिगोचर हो रही है । प्रभावित तो इसने हर उस व्यक्ति को किया है, जिसे अवसरों एवं पूँजी का सर्वथा से अभाव ही मिला, वही अवसर जो उसे अपनी श्रमशक्ति के बदले में आर्थिक स्वतंत्रता के रुप में प्राप्त हो सकता था । इस समस्या का हल व्यैक्तिक स्तर के साथ ही साथ सामूहिक एवं सरकारी सहयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । यदि सरकार अपने क्षेत्र की जनता को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, तभी बेरोजगारी की समस्या एवं इसके कुप्रभाव को लघु एवं बाद में नगण्य किया जा सकेगा ।

संदर्भ

1. CHAUDHARY, D. K. (2021). UNEMPLOYMENT STATUS IN VAISHALI DISTRICT OF BIHAR-A SOCIO- ECONOMIC PERSPECTIVE.

2. Kumar, A., & Kumar, M. (2020). Marginalised Migrants and Bihar as an Area of Origin. *Kerala Exp*, *55*, 21.

3. Sabreen, M., & Behera, D. K. (2020). Changing Structure of Rural Employment in Bihar: Issues and Challenges. *The Indian Journal of Labour Economics*, *63*(3), 833-845.

4. Chakravorty, B., & Bedi, A. S. (2019). Skills training and employment outcomes in rural Bihar. *The Indian Journal of Labour Economics*, *62*(2), 173-199.

5. Sinha, J. K. Economic impact of unemployment and inflation on output growth in Bihar during 1990–2019. *Statistical Journal of the IAOS*, (Preprint), 1-10.

6. Deshwal, A. (2017). Economic Growth and Poverty Reduction in Bihar During 2004-05 to 2011-12: Examining the Contradictions. *Available at SSRN 3009234*.

7. Srinivasan, T. N., & Allen, T. (2013). Some Aspects of the Trends in Employment and Unemployment in Bihar and Kerala since the 19705. *Economic Reform in India: Challenges, Prospects, and Lessons*, 319.

8. Venkatesh, P. (2013). Recent trends in rural employment and wages in India: has the growth benefitted the agricultural labours?. *Agricultural Economics Research Review*, *26*(347-2016-17099), 13-20.

9. Kashyap, K. K. D. P. (2005). Poverty Profile of Bihar: Some. *Poverty Alleviation in the Third World*, 310.

10.Bhattacharya, B. (2000). Bihar after bifurcation: A challenging future. *Economic and Political Weekly*, 3800-3804.

11. U.S. Bureau of Labor Statistics (2022). " How the Government Measures Unemployment ".

12. International Labour Organisation . (2013).

13.एन० एस० एस० ओ० इंपलॉयमेंट एण्ड अनइंपलॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट, नीति आयोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) , NSO

14. WWW.CEICDATA.COM|National Sample Survey Organisation

15.Reserve Bank of India, m.rbi.org.in

16.PLFS 2017-18,2018-19 and 2019-20 Surveys

17. Centre for Monitoring Indian Economy Pvt. Ltd.